VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन घंटे** | अधिकतम अंक: **250**
*Time Allowed: **Three Hours*** | *Maximum Marks: **250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0481289

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : ASHISH PUNIYA

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
हिन्दी

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

तारीख
Date
27/8/22

केंद्र
Centre MUKHERGEE NAGAR

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature
Priyanshi

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration .number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use

परीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of Examiner(s)

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISION IAS

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Do you agree with the view that time has come to revisit the Seventh Schedule of the Indian Constitution? Discuss with suitable arguments. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 से संबंधित है जो केन्द्रीय संसद एवं राज्य विधानसभा की विधायी सीमाओं को निर्धारित करती है।

सातवीं अनुसूची

- संघ सूची — 100 विषय
- राज्य सूची — 52 विषय
- समवर्ती सूची — 47 विषय

पुनर्विचार के पक्ष में तर्क

1. विभिन्न विषयों का अतिव्यापन की स्थिति विवादों को बढ़ावा
   - कृषि एवं विपणन
   - जल संबंधी sec-52 राज्य एवं sec-17 केन्द्र सूची

2. सातवीं अनुसूची में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति असममित संघवाद को बढ़ावा देती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. केन्द्रीय विषयों में लगातार वृद्धि हुई तथा राज्य विषयों में कमी।

4. समवर्ती सूची का केन्द्र द्वारा मनमाना प्रयोग

5. ऑल इंडिया सेवाओं का विकास में बाधाएँ → स्वास्थ्य, न्याय, शिक्षा

आगे की राह

→ सरकारिया आयोग ने समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय राज्यों से परामर्श की सिफारिश

→ समवर्ती पर कानून मात्र ठीक आवश्यक स्थितियों में (पुंछी आयोग)

→ व्यापक विमर्श।
↳ अंतर्सरकारी परिषद में

→ राजकोषीय संघवाद → GST परिषद में

सरकारिया आयोग ने मजबूत केन्द्रीकृत संघ के साथ संभावनाशील व दक्ष राज्यों की सिफारिश की है जबकि नीति आयोग ने ESI (empowered states of India) की परिकल्पना की है।

2. न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए, भारत में इसकें प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Highlighting the advantages of online dispute resolution (ODR) mechanism for justice delivery, discuss the challenges associated with its effective implementation in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

ऑनलाइन विवाद समाधान सेवाएं पारंपरिक न्याय एवं वैकल्पिक न्याय (ADR) से भी बढ़कर है जो न्याय के साथ परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है।

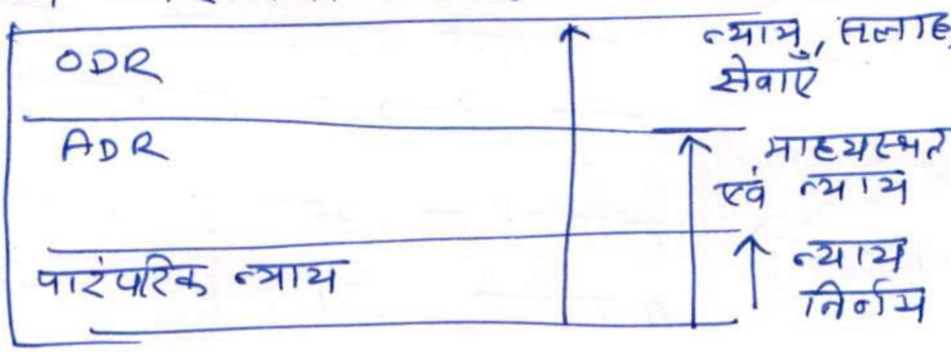

ODR के लाभ

① न्यायपालिका में विलंबित 4 crore से ज्यादा मामलों का निपटान

② ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

③ न्यायिक जागरूकता → विधिक सेवाओं का अभाव → 92% कैदी कमजोर वर्गों से

④ न्याय प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार डिजिटल इंफ्रा, तकनीक चालित सिस्टम, डिजिटली डोक्यूमेंटेशन

(5) ODR भारत को माध्यस्थम कैपीटल बनाने में सहायक

माध्यस्थम बिल 2021
→ कौन्सिलेशन
→ मीडिएशन
→ आर्बिट्रेशन
→ नेगोशिएशन

चुनौतियां

(1) तकनीकी लागत तथा ODR प्रणाली की व्यवहार्यता

(2) डिजिटल डिवाइड एवं डिजिटल साक्षरता का अभाव

(3) अधीनस्थ न्यायपालिका बुनियादी संरचना का जिम्मा राज्य सरकार → कमजोर Infra

(4) निजता संबंधी मुद्दे

(5) साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी

आगे की राह
→ 2024 तक ब्लॉक स्तर डिजिटल साक्षरता केन्द्र
→ न्यायपालिका अवसंरचना ग्रिड → SC के अधीन बजट एकीकरण
→ निजता / डाटा सुरक्षा कानून

CJI रमन्ना ने 2024 तक प्रत्येक जिले में नियुक्त Tally लॉ योजना के विस्तार की बात की। जो ODR को सार्वभौमिक बनायेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बावजूद, केंद्र-राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता रहे हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite the constitutional division of powers, Centre-state disputes have been a perennial feature of Indian democracy. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संविधान के भाग 12 में वित्तीय एवं भाग 11 में विधायी व प्रशासनिक शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है। फिर भी संघवाद की गतिशीलता के कारण विवाद मौजूद है।

1. अंतर्राज्य नदी जल विवाद – अनुच्छेद 262 में संसद द्वारा कानून बनाकर समाधान का प्रावधान
→ 1956 ISRWD एक्ट
→ 1956 नदीजल बोर्ड एक्ट
फिर भी समाधान नहीं → 2019 विधेयक

2. राजकोषीय संघवाद – GST को लेकर – क्षतिपूर्ति सेस का मुद्दा।
- राज्यों द्वारा उधारी का मुद्दा
- 15th वित्तआयोग → शर्तयुक्त अनुदान
→ 2011 की जनगणना
→ वित्त आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं

3. असममित संघवाद → अनु. 371
   ↳ एक देश एक चुनाव का मुद्दा
   ↳ क्षेत्रीय विषमता

4. वन नेशन वन लेंग्वेज का मुद्दा
   अनु० 351 (हिन्दी का प्रसार)

आगे की राह

- GST परिषद की बैठकों में राजकोषीय संघवाद के मुद्दों पर चर्चा (अबतक 47 बैठक - सफलता
- राज्य आधारित समाधान (Bottom up एप्रोच)
- वित्त आयोग में राज्यों की भागीदारी
- समय पर विवाद निपटान
- क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें।

बावजूद Covid-19 के दौरान केन्द्र व विभिन्न सीमाओं के राज्यों के समन्वित प्रयास उल्लेखनीय है। PM श्री मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद बैठक में "टीम इंडिया" के एकीकृत संरचना की प्रशंसा की।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4\. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लॉबिंग के लिए एक ढांचे को अंगीकृत करना भारत में सहभागी शासन और कारोबार सुगमता को सुदृढ़ करेगा? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Do you agree with the view that adopting a framework for lobbying will strengthen participative governance and ease of doing business in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

लॉबिंग एक रणनीतिक गतिविधि है जिसमें दबावसमूहों द्वारा अपनी मांगों, लक्ष्यों तथा हितों के लिए कार्यपालिका एवं संसद पर दबाव बनाया जाता है।

उदा० के लिए भारतीय डायस्पोरा लॉबिंग
⇓
भारत को NPT हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद USA सिविल न्यूक्लियर डील

लॉबिंग को अंगीकृत करना

1. सरकार एवं विभिन्न हितधारकों के बीच दूरी कम होना
2. तथ्य एवं फीडबैक आधारित नीति निर्माण
3. स्वच्छ राजनीति → ADR एवं PUCL द्वारा राजनीतिक शुचिता हेतु लॉबिंग

4. बंधुआ मजदूरों, बच्चों हेतु लॉबिंग एवं PIL

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. MSME की लॉबिंग → लघु व कुटीर उद्योगों का विकास

6. स्थानीय स्तर पर माइक्रोगवर्नेंस का विकास

सीमाऐं

→ सिविल सोसायटी का प्रयोग एक वारफेयर के रूप में (अजीत डोवाल NSA ने कहा

→ CBI ने कुछ वर्ष न्यायालय में कहा कि कुछ NGO राष्ट्रविरोधी गतिविधि में GDP में 2-3% नुकसान

→ राष्ट्रीय महत्व प्रोजेक्ट बाधित → कुडनकुलम, तूतीकोरिन स्टरलाइट

आगे की राह

→ IT act एवं FCRA आधुनिकीकरण (विजयकुमार कमेटी)

→ स्वैच्छिक संगठनों का विकेन्द्रीकरण

2nd ARC की 9th रिपोर्ट में कहा कि "सामाजिक पूंजी" का विकास करने व सहभागी जनतंत्र के लिए लॉबिंग व सामूहिक भागेदारी बुनियादी जरूरतें हैं।

5. सरकारी अनुप्रयोगों के लिए सरकार द्वारा प्रोपराइटरी (निजी स्वामित्व और नियंत्रण वाली) प्रौद्योगिकी के बजाय ओपन स्रोत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के बावजूद, फ़्री एंड ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर (FOSS) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite the government encouraging open source instead of proprietary technology for government applications, the true potential of Free and Open Source Software (FOSS) and digital platforms remains unrealized. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे उपकरण होते हैं जो उपयोग हेतु निर्बाध स्वीकार्यता प्रदान करते हैं तथा डिजिटल गवर्नेंस, डिजीटल पेमेंट तथा नागरिक सुलभता सुनिश्चित करते हैं।

उदा. के लिए → UPI, आरोग्यसेतु

सरकार द्वारा Foss को प्रोत्साहन एवं लाभ

1. UPI के प्रयोग से 2016 के 0.7 milion डिजिटल भुगतान की तुलना में 2021 में 3 billion भुगतान (RBI डिजिटलपेमेंटindex)
2. आरोग्य सेतु → Covid प्रसार रोकने में
3. CoVIN → वैक्सीन प्रत्यावर्तन मैनेजमेंट
4. डिजीलॉकर, GSTनेटवर्क
5. ग्राम संवाद एप्प

6. UMANG → Society, कॉमनसर्विससेंटर

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं

- डिजिटल डिवाइड → IP 90
  इंटरनेट पेनेट्रेशन

- तकनीकी अवहार्यता
  - ↳ इंटरनेट बाधित, डिजिटल सुरक्षा
- सरकारी मैसेजर एप्प के बजाय Whatsapp का प्रयोग
- डाटा क्लासिफिकेशन दुविधाएँ

आगे की राह
- → डिजिटल कॉमर्स हेतु DPIIT द्वारा ODNC का विकास
- → इंडियास्टेक
- → IndEA मानक
- → डाटा सुरक्षा कानून

इस दिशा में डिजिटल इंडिया के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने डिजिटल इंडिया जेनेसिस, इंडियाभाषिणी एवं इंडियास्टेक प्रोग्राम लॉन्च किए।

6. एक सामाजिक सुरक्षा-वाल्व के रूप में, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) प्रमुख साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से समुदाय अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
As a social safety-valve, non-governmental organisations (NGOs) can be the principal vehicles through which communities voice their concerns. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

NGOs गैर सरकारी समूह होते हैं जो विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं - वर्ल्ड बैंक के अनुसार

- → गरीबी निवारण
- → आय असमानता निवारण
- → पिछड़ों का कल्याण
- → पर्यावरण संरक्षण

सामाजिक सुरक्षा वॉल्व - NGO

- समुदायों में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक चिंताओं का निवारण
  - कुटुम्ब श्री
  - जय अंबे, राजस्थान
- ट्रांसजेंडर व HIV पीड़ितों के लिए

→ "कंचन केन्द्रे" के नेतृत्व NGO ने ट्रांसजेंडरों → वैक्सीन स्वीकार्यता (vaccine दीदी)

⇒ मणिपुर में (KHUDOL) → ट्रांसजेंडर, HIV पीड़िता, सेक्स वर्कर के लिए
- भोजन
- पोषण व दवाईयाँ
→ UNDP ने top-10 नवाचारी पहलों में शामिल

पर्यावरण के क्षेत्र में BNHS, सलन नागरिक जानकारी

मानव तस्करी पीड़ितों को कानून निर्माण (तस्करी बिल 2021) में शामिल करना
ILFAT (इंडियन लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग)

इस प्रकार से नेतृत्व स्रोत अपने समुदाय की आवाज बुलंद करने का साधन बनते हैं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. अपने रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सराहे जाने के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का कार्यान्वयन सुस्त है और विभिन्न मुद्दों से घिरा हुआ है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite being lauded for its patient centric approach, the implementation of the Mental Healthcare Act, 2017, remains sluggish and mired with various issues. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत कुल स्वास्थ्य खर्च का 0.5% से भी कम भाग मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है।

2017 का मानसिक स्वास्थ्य एक्ट ~~म~~ सुस्त

→ मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च नहीं बढ़ाना जाना

→ जनजातीय क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में कम पहुँच

मॉडल → मिशन बीरबाहा राज्य असम

→ मानसिक चिकित्सा कार्यकर्ता की कमी

→ Helpline किरण अप्रभावी

→ डिमेंशिया को अधिकता

आगे की राह

→ बुनियादी अवसंरचना

→ R&D

अनु० 47 राज्य को निर्देशित करता है नागरिकों के उन्नत स्वास्थ्य के लिए।

8. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना तैयार करने का समय आ गया है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that time has come to formulate an Urban Employment Guarantee scheme at the national level? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

MNREGA एक्ट 2006 की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी एक्ट की मांग उठ रही है।

मेघालय द्वारा जनगणना कस्बों व छोटे शहरों में मनरेगा लागू

राजस्थान व उड़ीसा द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

आवश्यकता

→ कमजोर बुनियादी ढाँचा

→ 17% शहरी आबादी मलिन बस्तियों में

→ PLFS - 2020 के अनुसार
बेरोजगारी → 5.2%

बेरोजगारी	गांव	शहर
	3.3%	6.7%

→ 2006-2016 के बीच मनरेगा
ने 271 million लोगों को
गरीबी से बाहर निकालने
में मदद

→ NULM, शहरी विकास
"नगर वन विकास" योजना
का कार्यान्वयन

UNDP द्वारा
मनरेगा को गरीबी निवारण की
वैश्विक प्रथाओं में शामिल किया
गया।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्सटेक की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of BIMSTEC as a regional organisation to fulfil India's strategic aspirations in the Indian Ocean Region. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्सटेक चार्टर को अपनाने पर सहमति बनी।

बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी में विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रीय सहयोग संगठन है।

महत्व

① सामरिक
↓
सागर रणनीति
↓
IORA तथा क्षेत्र में नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका

भारत
श्रीलंका
मालदीव
नेपाल
भूटान
म्यांमार
थाईलैंड

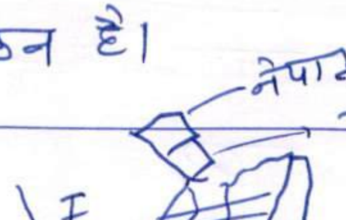

② समुद्री सुरक्षा एवं व्हाइट शिपिंग

③ कोस्टल एवं आंतरिक सुरक्षा
↳ CSC (कोस्टल सिक्योरिटी कान्क्लेव)
NSA स्तर → India → श्रीलंका मालदीव
• NSCN, ULFA से निपटना
उदा. म्यांमार में ऑपरेशन सनराइज

④ आर्थिक → कालादान, BBIN संपर्क
→ सप्लाई चैन विकास
→ चीन पर निर्भरता कम करना
→ लगभग 30 B$ का व्यापार

⑤ आपदा प्रबंधन → अर्ली वार्निंग, सुनामी सिस्टम, CDRI

⑥ चीन का प्रतिसंतुलन
→ BRI प्रभावित लगभग सभी देश - भारत को छोड़कर

सीमाएँ → चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल
→ सीमित क्षमता
→ लार्ड की तरह दक्षिण एशियाई साझा पहचान का अभाव
→ म्यांमार का JUNTA शासन
→ बांग्लादेश - शरणार्थी
→ नेपाल वामपंथ
→ श्रीलंका - दिवालियापन

इस संदर्भ भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एवं एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रासंगिक है जो क्षेत्र में शांति व प्रवीतर में विकास सुनिश्चित करेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. वर्तमान समय में अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में भारत के लिए गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of the Gujral Doctrine for India with regard to its relations with its immediate neighbours in the present times. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गुजराल सिद्धान्त पूर्व विदेशमंत्री इंद्रकुमार गुजराल द्वारा 2004 में प्रस्तुत किया गया। जो शर्तरहित सहायता के साथ पड़ोसी देशों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करता है।

गुजराल सिद्धान्त
- → बिना लाभ की प्रत्याशा सहायता
- → प्राकृतिक आपदा में त्वरित मदद
- → पड़ोस में शांति व समृद्धि
- → बिग ब्रदर सिंड्रोम को समाप्त करना

भारत के कदम एवं प्रासंगिकता → कोविड-19 के दौरान सभी पड़ोसियों को हाइड्रोक्लोरोक्वीनीन, वेक्सीन एवं COVIN एप्प प्रदानगी।

⇒ ऑपरेशन नीर 2014 मालदीव

⇒ श्रीलंका 2021-22 संकट के दौरान

रसद आपूर्ति एवं 3.25 b$ की आर्थिक मदद।

• नेपाल भूकंप एयरफोर्स द्वारा मदद

• वर्तमान में चीन के डेब्ट ट्रैप रणनीति व चेकबुक डिप्लोमेसी के दौरान गुजराल सिद्धान्त ज्यादा प्रासंगिक

• मालदीव तथा छोटे देशों की सीमित क्षमताएँ

• हिन्दमहासागर व हिमालय क्षेत्र में आपदाएँ

नीति की सीमाएँ
- → श्रीलंका, नेपाल, भूटान द्वारा मदद स्थिति का दुरुपयोग
- → श्रीलंका में चीन का सर्विलांस जहाज
- → भारत की विकास की अपनी सीमाएँ → India डोमिनेंस, चाइना पे की धारणा।

हालांकि भारत सरकार सभी पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी, HICDP (हाई इम्पैक्ट सामुदायिक विकास) तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. भारतीय संसदीय प्रणाली में "संसद के अधिकारियों" की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके निष्पक्ष कामकाज के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Highlight the pivotal role of the "Officers of Parliament" in the Indian Parliamentary system. Also, discuss the constitutional and statutory provisions for their impartial functioning. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 93 से 9~~8~~ तक संसद के अधिकारियों का उल्लेख है।

भूमिका → अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति

- लोकसभा एवं राज्यसभा में ~~[illegible]~~ कार्यवाही का निर्देशन
- संसदीय समितियों का गठन
- 10th अनुसूची (दलबदल) पर कार्य करते समय अधिकरण की तरह कार्य
- सदन में व्यापक वाद विवाद एवं चर्चा का वातावरण सृजन
- निजी विधेयकों पर चर्चा को स्वीकृति
- लोकसभा अध्यक्ष की विशेष क्षमता - धन विधेयक को नोटिंग करने में
- संसद में एकल सदस्य की भूमिका प्रभावी बनाने में

अर्थात इन पदाधिकारियों की लोकतंत्र को भीड़तंत्र बनने से रोकने में प्रभावी भूमिका है।

निष्पक्ष कामकाज के प्रावधान

1. संसदीय विशेषाधिकार → इन्हें गैर राजनीतिक माना जाता है।
2. दलबदल कानून से छूट → यदि ये राजनीतिक दल से इस्तीफा देते हैं
3. वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित
4. इनकी अनुपस्थिति में इनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पैनल के व्यक्ति द्वारा सभापतित्व।
5. हटाने का तरीका

LS स्पीकर	RS सभापति
↓	↓
साधारण बहुमत से ~~(~~	RS से पूर्ण बहुमत द्वारा 25 मात

6. सार्वजनिक बैठकों में वरीयता (order) सूची में कैबिनेट मंत्री से पहले स्थान

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

बाधाएँ

- दल-बदल कानून
  - 1991 → स्पीकर राजपार्टी द्वारा निष्पक्षता में अक्षम होने को स्वीकारना
- भारत में USA की तर्ज पर एकदा स्पीकर, सर्वदा स्पीकर की रणनीति नहीं।

स्पीकर व पदाधिकारी संसदीय व्यवस्था के ध्वजवाहक हैं इनकी निष्पक्षता लोकतंत्र की शुचिता का आधार है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में, 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The Finance Commission plays a crucial role in balancing fiscal federalism in India. In this context, examine the recommendations given by the 15th Finance Commission. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वित आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय है जिसे प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।

योग्यताएँ

अध्यक्ष - सार्वजनिक अनुभव
4 सदस्य → वित्त, लेखा, प्रशासन एवं न्याय योग्यताएँ

वित आयोग व राजकोषीय संघवाद

1. केन्द्रीय करों के पूल से धन को राज्यों को बंटवारा
↓
क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर

15th वित्तआयोग → 41% ~~कर~~ हिस्सा 2021 से 2026 तक राज्यों को

2. राज्यों के क्षेत्रीय विषमता, जनसंख्या बाध्यताओं का समाधान

क्षेत्रफल → 15%. मानक
जनसंख्या (2011) → 15%.
आय विषमता → 45%. मानक
कर प्रयास → 2.5%
पर्यावरण → 10%.
[3.] TFR डेमोग्राफी → 12.5%

3. उपरोक्त डाटा के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण (12.5%) एवं कर प्रयास (2.5%) को शामिल करके राजकोषीय संघवाद को बहुआयामी बनाता है।

4. वित्त आयोग संधारणीय विकास सुनिश्चित करने हेतु राजकोषीय मानकों में पर्यावरण को महत्व।

5. प्रदर्शन आधारित अनुदान
⇓
प्रतिस्पर्धी संघवाद

6. पंचायतों को तथा ULBs को 3.66 लाख करोड़ अनुदान राजकोषीय संघवाद के जमीनी

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए' Candidates must not write on this margin

स्तर तक विस्तार को दिखाता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सीमाएँ → राज्यों द्वारा 2011 की जनगणना की शिकायत
→ केन्द्र द्वारा केन्द्र को अनुदान
BMFDES (बिकेंद्र आधुनिकीकरण फंड)
→ सेस व सरचार्ज का बड़ा भाग गैर-हस्तांतरणीय
→ वित्त आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं
→ स्थानीय स्तरों तक धन के कम प्रसार तथा उपयोग पर जिला प्रशासन का केन्द्रीकरण

इस संदर्भ में
आगे की राह → वित्त आयोग को स्थायी निकाय
→ राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर सरकारों की पालना
→ अंतर्राज्य परिषदों में चर्चा
→ सहकारी संघवाद

13. आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन प्रदान करना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों में योगदान करेगा। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Critically assess whether according statutory backing to the Model Code of Conduct will contribute towards free and fair elections in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कार्मिक, न्याय एवं प्रशासन पर संसदीय स्थायी समिति ने MCC को RoPA एक्ट 1951 में विधिक दर्जा दिया जाने की सिफारिश की है।

पक्ष में तर्क

1. अनुच्छेद 324 के तहत ECI को प्रभावी बनाना
↓
1978 के मोहिंदर गिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा → चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव हेतु असीमित शक्तियों का अधिकारी है।

2. चुनावी मुफ्त उपहारों (freebees) पर नियंत्रण
वर्तमान → MCC के चेप्टर VIII में प्रावधान → लेकिन लागू करने की शक्ति

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. सभाओं के दौरान धार्मिक व जातीय वैमनस्य
⇓
सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव

4. MCC को वैधानिक बनाने तथा राजनीतिक दलों को विपंजीकृत करने की शक्ति से चुनाव आयोग मजबूत होगा

5. अत्यधिक एक्जिट, ओपिनियन पोल, पेड मीडिया चुनाव को प्रभावित करते हैं।

सीमाएँ → MCC चुनाव आयोग की शुरुआत नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा स्वतः अर्जित नैतिक पहल है।
→ MCC वैधानिक करने से सत्ताधारी दलों द्वारा अन्य दलों को प्रभावित करने का आरोप लगेंगे।
→ ECI की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे।

आगे की राह

- दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 MCC को मान्यता
- सर्वोच्च न्यायालय MCC को वैधानिक बनाने पर टिप्पणी
- ECI की स्वायत्तता सुनिश्चित करना
  - रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं
  - नियुक्ति प्रक्रिया में विविध लोगों की नियुक्ति

चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है तथा निष्पक्षता लोगों के भरोसे को कायम करती है इस दिशा TN शेषन व NN वोहरा का योगदान उल्लेखनीय है।

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14. डिजिटल क्रांति के कारण बाजार में आए व्यवधान ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नवीकृत फोकस और परिप्रेक्ष्य को आवश्यक बना दिया है। इस आलोक में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में सुधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The market disruption caused by digital revolution warrants renewed focus and perspective to ensure fair competition in the digital economy. In this light, discuss the need to revamp the Competition Commission of India (CCI). (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, 2002 में CCI अधिनियम के तहत सांविधिक निकाय है, जो MRTP एक्ट 1970 का स्थान लेता है।

हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति ने टिप्पणी की है कि 90% से अधिक ई-कॉमर्स बाजार अमेज़न व वालमार्ट 2 कंपनियों के पास है तथा समिति ने CCI में व्यापक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

(CCI में ~~सुधार~~ चुनौतियाँ)

1. विभिन्न प्रावधानों के बावजूद मोनोपॉली रोकने में सक्षम नहीं

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. डिजिटल एवं Telecom कंपनियों द्वारा कार्टेलाइजेशन
उदा॰ Vodafone, Jio, Airtel समान दरें।

3. CCI बड़ी कंपनियों एवं सरकारी अधिकारियों के गठजोड़ की जांच करने में सक्षम नहीं
→ अमेजन द्वारा उच्च अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने का मामला

4. CCI द्वारा बाजार मूल्यों के नियंत्रण व उपभोक्ता संरक्षण में अप्रभावी रहना

आगे की राह
→ कानून में सुधार
→ CCPA (उपभोक्ता संरक्षण प्रा॰) तथा CCI में समन्वय

→ व्हाइट कॉलर कार्मिकों की भूमिका में विस्तार की जाँच

→ व्यापक अभियोजन शक्तियाँ

→ जुर्माना व दंड में विस्तार

→ कार्यबल में नियुक्तियां, तकनीकि स्तर प्रशिक्षण

WEF ने कहा कि जिस स्तर गति से विभिन्न तकनीकें व डिजिटल कंपनियां प्रगति कर रही है उस अनुपात में देशों के कानून प्रगतिशील नहीं है अतः व्यापक बदलाव की आवश्यकता है)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. भारत में एक प्रभावी व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र और साथ ही यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में व्हिसल-ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

There is an urgent need for effective whistle-blowing mechanisms and ensuring that necessary safeguards for the protection of whistle-blowers are established in both public and private spheres in India. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 87 व्हिसल ब्लोअर्स की हत्या कर दी गई।

प्रमुख नाम - सत्येन्द्र दूबे
→ संजीव चतुर्वेदी
→ जगदीश कुमार चौधरी (हिरासत में मौत)

चिंताएँ

→ 2014 में कानून बनने के बावजूद अब तक कानून को नोटिफाई नहीं किया गया।

→ व्हिसल ब्लोअर की जानकारी गुप्त रखने का उल्लंघन करने पर मामूली सजा।

→ अनाम शिकायतों पर कार्रवाई

० निजी क्षेत्र में

↳ मार्क मेगानन द्वारा Uber india द्वारा पैनिक बटन की अकुशलता की शिकायत

↳ फॉक्सवेगन कंपनी द्वारा BS मानकों का उल्लंघन → ईंजन में खामियां

सुधार

→ कानून को Notify किया जाये

→ व्हिसल ब्लोइंग की शिकायतों की जांच तय सीमा में

→ निजी, सार्वजनिक, PPP तीनों में नियम बनाये जाए।

→ प्रशासन में शुचिता का विकास

↳ इंटीग्रिटी पैक्ट

↳ मिशन कर्मयोगी

व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा

1. व्हिसलब्लोअर की हत्या की जांच NIA द्वारा की जाए
(क्योंकि यह संगठित अपराध है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. NHRC की भूमिका को प्रभावी बनाया जाये
↳ सजा देने की शक्तियां

3. स्नोडेन व मार्क मेगानन गतिविधि से सीखते हुए निजी क्षेत्र के व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा, व आजीविका संरक्षण

4. व्हिसलब्लोअर के परिवार को संरक्षण (न्याय मंत्रालय की गवाह संरक्षण योजना की तर्ज पर)

5. NFT तकनीक द्वारा नाम की गुप्त रखना

वैंकेया नायडू कहते हैं जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के लिए अपने जीवन की परवाह न करके आगे आता है उसके हित में राज्य की भूमिका व्यापक हो जाती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. भारत में सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन के कारणों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इनकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
State the reasons behind the poor performance of cooperatives in India. Also, discuss the reforms undertaken by the government to overcome the shortcomings. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में सहकारी समितियों का गठन भाग 9 B (97th संविधान सं.) तथा अनु. 19(C) एवं 43 B के तहत होता है। ये राज्य सूची का विषय है व इनसे संबंधित कानून सहकारी पंजीयन एक्ट 1912 है।

खराब प्रदर्शन के कारण

1. राज्यों द्वारा 97th CAA को नहीं अपनाया जाना (Supreme कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया → राज्यों की बिना अनुसमर्थन पारित)
2. राजनीतिक हस्तक्षेप एवं स्वायत्तता का अभाव
3. धन व वित्तीय स्रोतों तक पहुंच नहीं
4. क्षेत्रीय विषमता
5. कौशल प्रशिक्षण नहीं

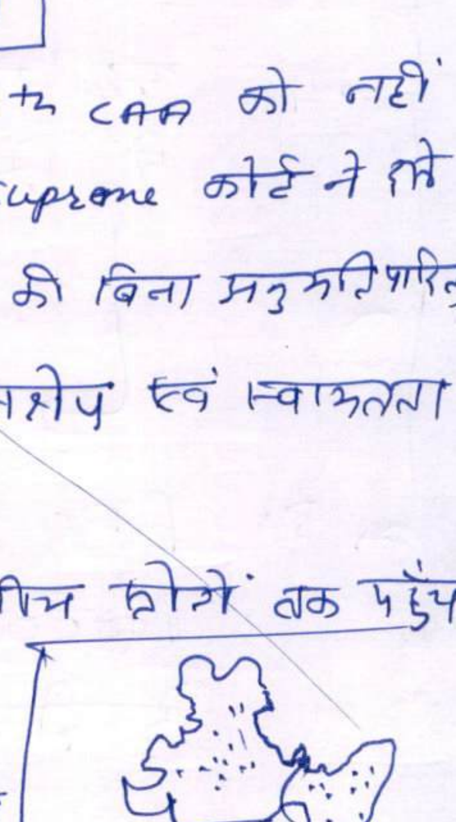

सरकार के कदम

→ 1. पृथक सहकारिता मंत्रालय (सहकार से समृद्धि की ओर

→ 2. मंत्रिमंडल द्वारा सभी PACs (प्राथमिक कृषि सहकारिताओं) का कंम्प्यूटरीकरण

→ 3. क्षमता विकास, ऋण प्रदान करने के लिए PSL मानदंड

→ 4. कई राज्यों में सरकारी योजनाओं में क्रियान्वन भागीदारी
  → छत्तीसगढ़ PDS वितरण
  → राजस्थान अन्नपूर्णा

→ 5. FPO के विकास के लिए 10000 ~~करोड़~~ करोड़ रु की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

हाल में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि

~~भारत~~ दुनिया पिछले 100 वर्षों से साम्यवाद एवं पूंजीवाद के बीच संघर्ष को देखती आई है लेकिन दुनिया को आगे ले जाने का रास्ता तीसरा मॉडल है वह "सहकारिता" है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17\. सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का यदि उचित तरीके से दोहन किया जाए, तो इसमें भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विद्यमान अंतराल को पाटने की क्षमता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Public-Private Partnership model, if harnessed properly, has the potential to bridge the gaps in India's healthcare system. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्रधानमंत्री ने कहा कि PPP मॉडल भारत का शासन व लोगों की भागीदारी का प्राचीन उपकरण है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। (पंजाब में PPP कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के दौरान)

PPP मॉडल के लाभ

1. निजी क्षमता की मशीनरी, प्रबंधकीय कौशल का दोहन
2. सरकारी सहयोग तथा निजी वित्तपोषण
3. लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवा
4. राज्यों की भूमिका नवलोकप्रबंधन के अनुरूप सेवा प्रदाता से सुविधा प्रदाता की ओर।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(5) आयुष्मान भारत का लाभ
↳ पूर्वोत्तर भारत में अस्पताल कम, लोगों को लाभ नहीं
⇓
टाटा एंड संस द्वारा पूर्वोत्तर में अस्पताल निर्माण की जिम्मेदारी प्रशंसनीय

(6) अम्माआनंदमयी माता द्वारा फरीदाबाद में एशीया का सबसे बड़ा अस्पताल

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वास्थ्य हेतु
→ इन क्षेत्रों जहां स्वास्थ्य सेवाएं बाधित, पूर्वोत्तर, मरुस्थल (थार), लद्दाख में PPP पर अस्पताल निर्माण
→ स्वास्थ्य पर 2.5% खर्च
→ AI मेडिकल सेवाएँ

PPP के स्वास्थ्य मॉडल की सीमाएं
(1) क्षेत्रीय विषमता
↳ अधिकतर अस्पताल दिल्ली, चेन्नई, दारीग मात्र बड़े महानगरों में

② जनजातीय क्षेत्रों में केवल प्राथमिक स्तर सेवाएँ

③ मेडिकल एथिक्स के मुद्दे

→ OGJ में निजी PPP अस्पताल द्वारा फर्जी बिल (आयुष्मान भारत) का मुद्दा।

→ ② 70% सिजेरियन डिलिवरी निजी अस्पतालों द्वारा

आगे की राह
→ हेल्थ & वेलनेस सेंटर अपग्रेडेशन
→ PPP कार्यक्रमों पर ad hoc अस्थाई प्रावधानों के बजाय दीर्घकालीन दृष्टिकोण
→ PPP ऑडिटिंग
→ CSR का प्रयोग

PPP मॉडल, VGF तथा आयुष्मान भारत के तहत अस्पताल विकास, दवा उद्योग भारत को आरोग्य राष्ट्र बना पायेंगे तथा मेडिकल डेस्टिनेशन में स्थान प्रदान होगा।

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

18. यद्यपि नई शिक्षा नीति अपने साथ एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लेकर आई है, इसकी सफलता सरकार की अन्य नीतिगत पहलों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत होने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Although the New Education Policy brings with itself a commendable vision, its success will depend on its ability to effectively integrate with the government's other policy initiatives. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में नई शिक्षा नीति को आए 2 वर्ष पूर्ण हुए। यह शिक्षा नीति पूर्व की 1986 की नीति का स्थान लेती है।

प्रशंसनीय दृष्टिकोण

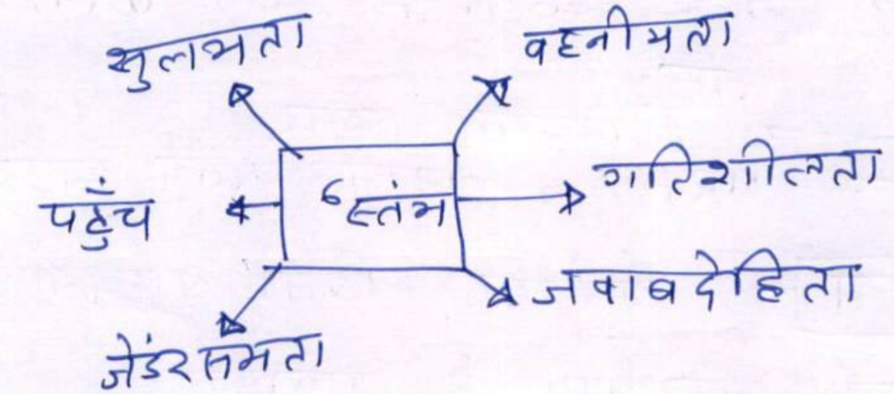

① पाठ्यचर्या
5+3+3+4 प्रणाली जो अर्ली चाइल्ड केयर एवं एजुकेशन को प्राथमिकता में रखती है।

② छोटे स्तरों पर दूरस्थ शिक्षा NIOS 5th व 8th क्लास पर

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

③ जेंडर समता फंड एवं दिव्यांग समावेशिता कोष

④ GER अनुपात 2030 तक 97% से 100% का लक्ष्य

⑤ NCEVT → 6th कक्षा से वोकेशनल शिक्षा

उच्च शिक्षा

- → मल्टी इन - एग्जिट, क्रेडेंशियल बैंक प्रणाली
- → शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण
- → GER 26% से 50% करना 2035 तक
- → विनियमन सुधार
- → NRF → नेशनल रिसर्च फांउडेशन

अन्य → त्रिभाषा, बिना बाध्यता के

- → मातृभाषा में प्राथमिक
- → दिव्यांगों के लिए नेशनल साइन लैंग्वेज
- → SEZ (स्पेशल एजु. जोन
- → GDP का 6% खर्च

सफलता में बाधाएं

- शिक्षा ~~समन्व~~ पर राज्यों व केन्द्र में पर्याप्त समन्वय
- GDP का 4% लगभग खर्च

- अन्य पहलों के साथ एकीकृत नहीं
  - ↳ पोषण, आंगनवाड़ी, आयुष्मान भारत
- शिक्षक प्रशिक्षण मानक बाधाएँ
- शिक्षक भर्तियों में भ्रष्टाचार → WB पार्थ चटर्जी
  - ↳ राजस्थान रीट लेवल-1

आगे की राह
- → अन्य योजनाओं के साथ समेकन
  - ↳ DDU ग्रामीण कौशल
  - → पेयजल मिशन
  - ↳ MDM व पोषण 2.0
- → ऑल इंडिया एजु. सर्विस गठन (UPSC)
- → समान मानक क्षेत्रीय क्षमताओं, मॉडल से सीखना

2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कौशलयुक्त शिक्षा पहली आवश्यकता है तथा यह SDG 4 (Quality education) को भी पूरा करेगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

19. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न हुआ है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में भारत की चिंताओं की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) is born from a collective desire to make the Indo-Pacific region an engine of global economic growth. Comment. Also, discuss India's concerns in this context. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत ने USA समर्थित IPEF में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह संगठन प्रशांत-हिन्द क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के सुनियोजित विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

IPEF और अवसर

1. भारत को हिंद महासागर में नेट सुरक्षा प्रदाता बनने के साथ-साथ इस क्षेत्र का ग्रोथ इंजन बनने का अवसर
2. समुद्री व्यापार संवर्धन एवं सुरक्षा
3. ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया तक विस्तृत व्यापारिक संबंध
4. तकनीक हस्तांतरण → सतत मत्स्यन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु।

5. QUAD को सामरिक सुरक्षा संगठन बनाने के बजाय व्यापारिक संगठन बनाने पर ध्यान केन्द्रित।

6. सप्लाई चेन रेजीलिएन्स इनीशिएटिव (SCRI)

7. <u>चीन के प्रभुत्व का सामना</u>

↳ चीन व्यापार के नाम पर भारत के पड़ोसी देशों में <u>सर्विलांस</u> जहाज भेजता है

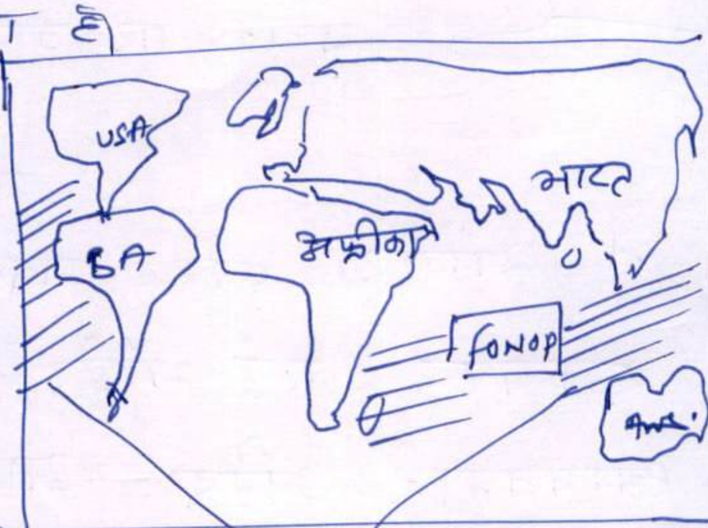

IPEF रीजन

उत्पन्न चिंताएं

① अमेरिकी प्रभुत्व

② USA द्वारा लॉजिस्टिक समझौता का पालन नहीं

③ USA ने FONOP (फ्रीडम ऑफ नेवल ऑपरेशन) के नाम पर हिंद महासागर (भारत के EEZ में जहाज

④ USA ने UNCLOS को Ratify नहीं किया जबकि China ने Sign नहीं किया

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⑤ China द्वारा खतरा माना जाना जाना।

⑥ इंडो पेसिफिक के गोल्डकोस्ट बनने का खतरा

- आगे की राह
  - → सहयोग
  - → नियम आधारित व्यवस्था
  - → चीन प्रभुत्व का मुकाबला
  - → UNCLOS पर प्रतिबद्धता

भारतीय प्रधानमंत्री ने शांगरी ला डायलॉग 2018 में रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, रणनीतिक स्वायत्तता और ओशियन फॉर ऑल का आह्वान किया।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20\. विस्तृत होते डिजिटल स्पेस और नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं के बीच भारत को अपनी तकनीकी-कूटनीति (टेक्नो-डिप्लोमेसी) को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
India needs to identify the priority areas to further its techno-diplomacy amidst the complexities of expanding digital space and New and Emerging Strategic Technologies. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

टेक्नो-डिप्लोमेसी का तात्पर्य है कि उभरती नवीन प्रौद्योगिकी के मद्देनजर राष्ट्रीय हितों के अनुकूल विदेशनीति का प्रावधान।

इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में NEST प्रभाग (न्यू इमार्जिंग साइंस एंड टेक) का गठन किया गया।

विस्तृत डिजिटल स्पेस

* 1 अरब मोबाइल फोन यूजर, 700 मिलियन इंटरनेट प्रयोगकर्ता

* 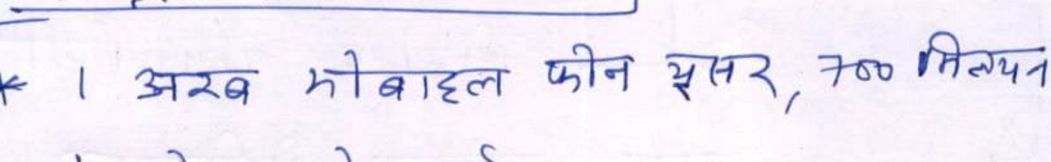

* 2016 में 0.7 million डिजिटल भुगतान 2021 में 3billion पार

नई तकनीकें
- IOT,
- AI, cyber फीजीकल सिस्टम
- 5G एवं सेमीकंडक्टर सेमीकण्डक्टर
- AR, VR, मेटावर्स
- Web 3.0
- Robotics, space,
- क्रिटिकल मिनरल्स एवं Renewable tech.

जरूरी क्षेत्रक

- 1. Telecom. सर्वाधिक यूजर
- 2. खाद्य प्रसंस्करण एवं विनिर्माण
  - नैनोइमल्शन
  - सिंथेटिक बॉयोलॉजी
- 3. रक्षा विनिर्माण, सेमीकंडक्टर
- 4. स्पेस → SSLV, चंद्रयान-4 जापान के साथ
- 5. नाभिकीय संलयन → ITER, LIGO
- 6. कृषि एवं ड्रिप सिंचाई → इजराइल से सहयोग

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. खेल प्रौद्योगिकी → जापान से सहयोग

8. Renewable → पंचामृत लक्ष्य

सीमाएँ → भारत को I-MSP अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से बाहर
- → चीन का प्रभुत्व → 5G हुवावे
- → चीन संप्रभुता → 200 mobile एप्प बैन
- → डिजीटल डायलॉग

भारत को नई tech. में राष्ट्रीय मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ-साथ USA के क्लाउड एक्ट तथा EU, GDPR की तर्ज पर डाटा सुरक्षा कानून पर ध्यान देना आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK